

संपादकीय

पूर्ण राज्यत्व की पूर्णता

आधी सदी का इतिहास और सबक हिमाचल के भविष्य की कल्पना में सुखखु सरकार के अगले पांच साल के सफर को खर रहे हैं, लिहाजा अपने पहले शासकीय संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्ण अन्यत्व दिवस का श्रृंगार किया है। सरकार ने 'एरिया ऑफ एक्शन' चिन्हित करते हुए पहले ही ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जबकि विवस्था परिवर्तन के तहत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का निलंबन, सीमेंट उद्योग पर नकेल, मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल तथा 101 करोड़ की सुख आश्रय जैसी दूरगामी योजनाओं का श्रीगणेश किया है। हिमाचल सरकार ने पूर्व में घोषित नौ सौ के करीब दफतर या सरकारी संस्थान बंद करके फड़क संदेश दिया है, तो नई उपलब्धियां जोड़ने के लिए अपने मंत्रियों व मुख्य संसदीय सचिवों की टीम बनाई है। किसी भी सरकार से विकास की अपराधाओं और कल्याणकारी योजनाओं की गिनती करते हुए हिमाचल ने कई विल पत्थर स्थापित किए हैं, लेकिन ये दौर खाने पर इतने महंगे साबित हुए कि आज 75 हजार करोड़ का ऋग्न सारे इरादों को बांध देता है। जाहिर है कुछ केजूल स्थिरियां हुईं या सियासी तौर पर संसाधनों की बंदरवांट होती रही, जो आज आर्थिक तंगी के मुहाने तपने लगे हैं। अतः सुखखु सरकार के हाथ अगर

हिमाचल सरकार ने पूर्व में घोषित
नौ सौ के करीब दफ्तर या
सरकारी संस्थान बंद करके
कड़क संदेश दिया है, तो नई
उपलब्धियां जोड़ने के लिए अपने
मंत्रियों व मुख्य संसदीय सचिवों
की टीम बनाई है। किसी भी
सरकार से विकास की परंपराओं
और कल्याणकारी योजनाओं की
गिनती करते हुए हिमाचल ने कई
मील पथर स्थापित किए हैं,
लेकिन ये दौर खजाने पर इतने
महंगे साबित हुए कि आज 75
हजार करोड़ का ऋण सारे इरादों
को बांध देता है। जाहिर है कुछ
फिजूल खर्चियां हुईं या सियासी
तौर पर संसाधनों की बंदरवांट
होती रही, जो आज आर्थिक तंगी
के मुहाने तपें लगे हैं। अतः
सुकखु सरकार के हाथ अगर
आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत दे रहे
हैं, तो प्रदेश के पांचों में भारी ऋण
की बेडियां जख्म पैदा कर रही हैं।

हत उम्मीद भी रहेगी कि मुख्यमंत्री प्रदूषिति दें, जो राजनीतिक कारणों से वाच्या धन अनुपयोगी साबित हो रहा है। नईनुः नई कसौटियां तय कर रहा है मल जाए, तो संकट कम होंगे या रहेंगे। हमाचल को अगर संपन्न होना है तो टार्टार्ट अपराज्य बनना पड़ेगा। यह संवाद ललते हुए विभागीय लक्ष्य तय होंगे। कूल, कालेज और विश्वविद्यालय भगर पांच सालों में नए संस्थान खोलेंगे और सरकारी क्षेत्र में गुणवत्ता आण्डी वथा ताजगी देने के इरादे से मुख्यमंत्री के केया है। रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन कारक कुछ छास करने की मंशा इपलब्धियों के लिए हूमैनिटीज के देश में विज्ञान या इंजीनियरिंग कालांत्रित प्रदान करने की जरूरत विकेट सेशन कुछ इस तरह चलाए गाननविद व जज पैदा हों। तकनीकी कालजों का स्तर उठाने की जरूरत पैदा हो। पूर्ण राज्यत्व से पूर्णता के लिए, नेटवर्किंग, जलापूर्ति, शिक्षा-चिकित्सा विसिल किया, उसमें गुणवत्ता लक्षणेविटियी की दृष्टि से ढाँचावत्ता विभाग और स्वरोजगार के आधार को पूर्ण रूप से शिखला एयरपोर्ट तथा मौजूदा हवाई अड्डों को विसिल करते तो दिशाएं बदल रियोजना की जयमाला पहनने की उदाहरण के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट मधु की प्राथमिकता के नाश्वून न रुफिला आज किसी अन्य मंजिल प

बोध कथा

प्रकृति के सौंदर्य का गुणगान करती है वसंत
ऋतु, संपूर्ण प्राणियों को देती है नई ऊर्जा

माध महीने का हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में विशेष महत्व है। इसी महीने की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी, सरस्वती आराधना और आविर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी के पर्व से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। संपूर्ण वसुधा का प्राकृतिक वातावरण दुल्हन के समान सजकर समस्त प्राणियों को आनंदित करने के लिए तैयार हो जाता राजद्रोह का भागला दिन किया सकता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है जिसके हतातीन साल से लेकर उप्रैक्ट तक की सजा का प्रावधान है।

। वसंत को त्रृतीयों का राजा कहा गया है। संपूर्ण धरती इन दिनों में एक अलग भी रंग में होती है। प्रकृति का सौंदर्य इस त्रृतीय में अपने चरम पर होता है। आज के दिन पृथ्वी की अग्नि सृजनता की तरफ अपनी दिशा करती है। इसलिए गरद त्रृतीय में मंद पड़े समस्त पेड़-पौधे, फूल, मनुष्य अपनी आतंरिक अग्नि को अज्जविलत कर नए सृजन की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस रमणीय त्रृतीय में कोयली अपनी मधुर कूक से प्रकृति के सौंदर्य का गुणगान करने लगती है। वसंत त्रृतीय संपूर्ण प्रकृति को नवगात, नव पल्लव, नव कुसुम के साथ विलक्षण उपहारों से अलंकृत करती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वसंत पंचमी को सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना गया है। माघ मास की पंचमी ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित उत्सव है। सरस्वती हमारी परम चेतना है। हमारे आचार और मेधा का आधार यही उत्सव है। ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती की प्रतिमा और वस्त्र आभूषण आदि में प्रतीकात्मक रूप से अनुकरणीय संदेश समावेशित है। सरस्वती का वाहन हंस विवेक शक्ति और सत्य-असत्य की पराख का प्रतीक है। मनुष्य को भी अपनी मनोवृत्ति हंस के समान विवेकशील बनानी चाहिए। इन्होंने में पुस्तक और निरंतर सद ग्रंथों के स्वाध्याय की प्रेरणा देता है। संफेद धबल वस्त्र सात्विकता और पवित्रता के परिचायक हैं। सरस्वती की वीणा हमें जीवन में संदैव मधुर संगीत के स्वरों की भाँति आनंद और उल्लास के वातावरण को पृथ्वीत करने का संदेश देती है। इस प्रकार सरस्वती आराधना का यह उत्सव नवनुष्य को विवेक, शक्ति से परिपूर्ण कर निरंतर आध्यात्मिक शास्त्रों के विवेतन, मनन से अपने जीवन को सात्विक, पवित्र बनाने का संदेश देता है। विवेदिक ग्रंथों में सरस्वती को वाङ्देवी, कामधेनु और समस्त देवों की प्रतिनिधि शक्ति माना गया है। इस त्रृतीय को मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण प्रकृति में वसंत त्रृतीय का यह समय मधुरता का संचार करता है। वसंत प्राकृतिक अग्निया के नवीनीकरण और पुर्नजन्म का समय है। यह प्रकृति को उसकी नींद नै जगाता है और उसे फिर से सक्रिय बनाता है।

मुलायम को पद्म विभूषण से नवाजे जाने का विरोध नहीं कर सकता है
मुलायम को पद्म विभूषण दिये जाने की घोषणा ने यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया

अजय कुमार

6

अयोध्या में परिदा भी पर हनीं
मार पाएगा। ऐसा हुआ भी।
1990 में जब कुछ राम भक्त
कार सेवक 'सौगंध राम की खु
हैं मंदिर वहीं बनाएंगे' का नारा
लगाते हुए अयोध्या हपुंचे तो
तत्कालीन सरकार के मुख्यमं
मुलायम सिंह यादव ने विवादि
ढांचे को बचाने के लिए उग्र हो
कार सेवकों पर गोली चलाने से
भी पहरेज हनीं किया था। जिस
सरकारी आंकड़ों के अनुसार
कार सेवकों मौत हो गई थी
लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के
अनुसार हय संख्या काफी
अधिक थी। इतना ही हनीं, बाब
में भी वह निः संकोच हक्कते हरे
कि बाबरी मस्जिद को बचाने ते
लिए उन्हें और गोली चलाने से
भी पहरेज हनीं होता।

क्या लोकतंत्र की यही खबां है कि भारतीय जनता पार्टी की उस केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सभा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जैसे नेता का नाम पद्धति विभूषण के लिए चुना गया जिनकी विचारधारा भाजपा की सोच से एकदम विपरीती थी? कौन भूल सकता है 1990 के उस दौर को जब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का संकल्प लेकर पूरे देश में यात्राएं कर रही थी, तब तत्कालीन मुलायम सरकार ताल ठोक रही थी कि बाबरी मस्जिद को बचाएगी। अयोध्या में परिदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसा हुआ भी। 1990 में जब कुछ राम भक्त कारसेवक 'सौंगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे' का नारा लगाते हुए, अयोध्या पहुंचे तो तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विवादित ढांचे को बचाने के लिए उग्र हो रहे कारसेवकों पर गोली चलाने से भी परहेज नहीं किया था। जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16 कार सेवकों मौत हो गई थी लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या काफी अधिक थी। इतना ही नहीं, बाद में भी वह निःसंकोच कहते रहे कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए उन्हें और गोली चलाने से भी परहेज नहीं होता। भले ही 16 की जगह 16 सौ कारसेवक मर जाते। मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे जीवन में कभी इस बात का पछतावा नहीं किया कि उनके आदेश के चलते दर्जनों राम भक्त मारे गए थे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुलायम सिंह यादव पर आक्रामक रहती थी। कारसेवकों पर गोली चलाने के कारण मुलायम सिंह हमेशा बीजेपी के कट्टर राजनीतिक दुश्मन बने रहे। लेकिन इसका मुलायम सिंह यादव के व्यक्तिगत जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके सभी पार्टीयों के नेताओं से अच्छे संबंध थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक से वह अपने दिल की बात खुलकर कहते थे। इतने अच्छे संबंध तो उनके कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी तक से नहीं रहे थे। सब जानते थे कि मुलायम सिंह की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग उनसे हमेशा नाराज रहता था और उनके खिलाफ वोटिंग करता था। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहकर पुकारा जाता था लेकिन इस सब बातों से बेफिक्र मुलायम हमेशा मुसलमानों के



प्रिय बने रहे। यहां तक की कई मुस्लिम नेताओं पर उनकी विरादी के लोग इतना भरोसा नहीं करते थे जितना मुलायम सिंह पर उनको भरोसा था। ऐसे नेता को जब मोदी सरकार में पद्म विभूषण से नवाजा जाता है तो सबाल तो उठेंगे ही। बहरहाल, इसके विपरीत कुछ बुद्धिजीवियों का अपना तर्क है। वे कहते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस घोषणा के दूरागमी परिणाम से इंकार भी नहीं किया जा सकता। गणतंत्र दिवस की पर्वं संध्या पर केंद्र सरकार ने वैचारिक तौर पर धूर विरोधी और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति के प्रमुख चैररे रहे पर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रबल प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के प्रमुख और मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव के लिए मुरिकलतों खड़ी कर ही दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भी भाजपा की इस चाल की काट तलाशना आसान नहीं होगा। फिलहाल समाजवादी के कई बड़े नेता और मुलायम की सांसद बहू डिंपल यादव ने अपने संसुर को दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार को नाकाफी बताते हुए नेताजी को भारत रत्न देने की मांग शुरू कर दी है। जबकि आज से पहले सपा की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी। खैर, यह कड़वी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता चाहते हुए भी मुलायम को पद्म विभूषण से नवाजे जाने का विरोध नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से की गई यह घोषणा उत्तर प्रदेश में भाजपा की पिछड़ों की लामबंदी और उनको और करीब लाने के मुहिम में मददगार

साबित होगी। यहां मुलायम से जुड़े एक और घटनाक्रम पर भी चर्चा करना जरूरी है। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच न सिर्फ कांग्रेस का यूपी से बोरिया विस्तर समेटने में प्रमुख किरदार रहे, बल्कि अयोध्या आंदोलन में उनकी भूमिका ने हिंदुत्व की विचारधारा से जन्मी भाजपा को भी अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में मदद की थी। धूर विरोधी होने के बावजूद कई मौकों पर मुलायम और भाजपा के बीच काफी नजदीकी रिश्ते भी देखने को मिले। इन रिश्तों ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी काफी उथल-पुथल की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता का मुद्दा उठाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का विरोध हो या लखनऊ का साड़ी कांड, मुलायम ने बताये मुख्यमंत्री पूरा मामला शांत कराकर लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से अटल बिहारी वाजपेयी के मददगार की भूमिका निभाई थी। वैचारिक व राजनीतिक दोनों ही स्तर पर विरोधी होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कई मौकों पर मुलायम की नजदीकी खबरों की सुर्खियां बनती रहीं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भरे मंच पर सबके बीच नरेंद्र मोदी के कान के पास जाकर मुलायम के कुछ फुफुसाने की घटना को कौन भूल सकता है? मोदी ने पहली बार जब शपथ ली तो मुलायम ना केवल शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे बल्कि मोदी ने भी उनको हाथों-हाथ लिया था। यह भी लोगों को याद ही होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में खुद जिस तरह नरेंद्र मोदी को फिर जीतकर आने और सरकार बनाने की शुभकामनाएं दी थीं उसने भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत हलचल पैदा की थी। प्रधानमंत्री मोदी मुलायम के परिवारिक फंक्शन में भी मौजूद रह चुके हैं। यह घटनाएं बताती हैं कि मुलायम और मोदी कितन करीब थे। बात समा जवादी पार्टी के मौजूदा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मोदी और भाजपा के साथ रिश्तों की करी जाए तो उनके रिश्तों में पिता मुलायम सिंह की तरह बीजेपी के प्रति नरम रुख नजर नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी और मोदी तमाम चुनावों में लगातार अखिलेश को पटखनी दे रहे हैं।

अंग्रेजो के जमाने का काला कानून आजाद भारत का लाड़ला क्यों हैं?

मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा करीब डेढ़ सदी पुराने अधिकारों को बदलना कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजों के जमाने में बनाए गये इस बदलानम कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को इंडियन पेनल कोड (भारतीय दंड संहिता) की धारा 124ए के तहत कोई भी एफआईआर दर्जना करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने तक के लिये है जिसका मतलब था कि अगर इस दौरान अगर राजद्रोह का कोई नया मामला दायर किया जाता है तो आरोपित व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को उम्मीद देने का काम किया है जो इस कानून की वजह से लंबे समय से जेल में हैं, यह एक लम्बी सूची है जिसमें कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता और युवा शामिल हैं। दरअसल डेढ़ सौ साल पहले 1870 में प्रभाव में आने के साथ ही यह कानून विवादों में रहा है। पहले अंग्रेजों द्वारा अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया और अब आजाद हिन्दुस्तान के हुक्मरान भी यही करते आ रहे हैं। खास बात यह है कि हम ब्रिटिश सरकार के गुलामी के दौरान के जिस कानून को अभी भी ढोते आ रहे हैं उससे खुद ब्रिटेन द्वारा साल 2009 में अपना पीछा छुड़ा लिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में “राजद्रोह” को परिभाषित करते हुये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसे किसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है जिसके तहत तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। गैरतलब है कि राजद्रोह कानून की अवधारणा ब्रिटिश सामाज्य की देन है जोकि 17वीं सदी में सामाज्य के खिलाफ उठी आवाजों को दबाने के लिये लाया गया था। भारत में तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा इस कानून को 1870 में लागू किया गया था। जिसका मुख्य मकसद ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करने वाले भारतीय क्रांतिकारियों को रोकना और उन्हें परेशान करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ किया गया था। आजादी के लड़ाई के दौरान कई राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इस कानून को हटाने की बात कही गयी थी लेकिन दुर्भाग्य से आजाद भारत के संविधान में भी धारा 124A को जोड़ा दिया गया। खुद जवाहर लाल नेहरू जैसे नेता की सरकार द्वारा “आजादी पर तर्कपूर्ण प्रतिबंध” के नाम पर बोलने की आजादी को सीमित करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया। इसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देशद्रोह को ‘संज्ञेय अपराध’ (ऐसा अपराध जिसमें गिरफतारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है) बना दिया गया। इस तरह से राजद्रोह कानून

लालिक गोपा

ਜਨਿਲਾਓ ਕੇ ਸਾਥ ਫ਼ਰਕਾਰੀ ਤੀ ਘਟਨਾਓ ਮੋ ਬਣੋਤਰੀ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਿਏ ਘਾਤਕ

देश मे दुष्कर्म की घटनाओं मे दिनप्रतिदिन इजाफा हो रहा है हर दिन अखबार मे दुष्कर्म की घटनाओं को पढ़कर सिर शर्म से झुक जाता है। भारत मे चिनोनी हरकतों से हरकोई स्त्रीय। अपनी सुरक्षा खुद करने की सीख हमेशा अभिभावक बच्चों को देते आ रहे हैं। लेकिन कड़नैपिंग के जरिये सामृहिक दुष्कर्म की घटनाओं वृद्धि देखने को मिल रही है। यह भारतीय संस्कृति लिए काला अध्याय है। जबर्दस्ती दुष्कर्म की घटनाओं मे देश के कानून मे फांसी का प्रवधान है और दुधमुही बच्ची के साथ दुष्कर्म और बारह साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना मे फांसी की जाका का कानून है उसके बाद भी दुष्कर्म हद से यादा अपराध कर रहे हैं। जिसका समाज को नफसोस है। देश मे राजस्थान मे गैंगरेप की घटना ढटी जा रही है। दौसा जिले मे बीस वर्ष की युवती ने जबर्दस्ती उसके गांव के दो लड़कोंने जंगल मे लाकर दुष्कर्म कर गांव के बाहर युवती को पटक कर गए। युवती की आपबीती पर थाने मे उन दुष्कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2013 मे क्रिमिनल लो अमेंडमेंट ऑर्डरनेस आया था। जिसमे फांसी के प्रावधान शामिल किए गए। 113890 दुष्कर्म हुए हैं। 2020 से 2022 मे 2243 केस दर्ज हुए हैं। राजस्थान दुष्कर्म के मामले मे सबसे आगे है। वहा बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। 16191 चालान हुए हैं जिसमे 4772 एकआईआर दर्ज की गई है। 620 दोषियों को सजा हुई है। इसमे आठ अपराधी को फांसी की सजा कोर्ट ने दी है। 137 से अधिक अपराधियों को उम्रकैद हुई। राजस्थान मे 2021 मे 6337 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। इस क्रम मे 2020 मे 5310 मामले प्रकाश मे आए हैं। यह चोकाने वाली घटना है कि राजस्थान मे महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं रही है। पुलिस की पकड़ नहीं होने से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 मे राजस्थान मे दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 2021 मे 2947 बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं। 2021 मे इन राज्यों के बाद महाराष्ट्र, यूपी और

असम में भी क्रमशः दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। इस विनोनी हरकतों में ये राज्य भी पीछे नहीं है। इन राज्यों में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इन दुष्कर्मियों को कानून और सजा का कोई डर नहीं है। यूपी 2845, महाराष्ट्र 2496, असम 1733 और दिल्ली में 1250 दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2020 में राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में टॉप पर था। राजस्थान में पिछले तीन साल में महिला हिंसा के मामले में अव्वल है। देश में रेप का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यह देश के लिए खतरनाक है। हररोज देश में महिला युवती और नाबालिगों को हवस का शिकार बनाने के बाद भी भेड़ियों को देश के कानून का डर नहीं गया 10.9 प्रतिशत दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है जबकि बाकी अपराधी हाथ नहीं लगे हैं। खुले धूम रहे हैं यह शर्म की बात है कि विश्व गुरु बनने वाले भारत में दुष्कर्म की घटनाएं हररोज मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं। संयम का पालन करना चाहिए। चोट करने की जगह पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

तमिलनाडु का मतलब है तमिलों का प्रदेश। तमिलगम का अर्थ है तमिल लोगों का निवास। 1938 में पहली बार द्रविड़ अंदोलन के जनक पेरियार रामास्वामी ने तमिलगम शब्द का इस्तेमाल किया था। DMK दरअसल शूरू में तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करती रही है। ऐसे में उसने मौन रूप से इस शब्द का समर्थन किया। मगर राज्य का नाम तमिलनाडु रखे जाने के बाद उसने अलग राष्ट्र की मांग छोड़ दी। अब इसी नाम का उठाकर राज्यपाल आरएन रवि ने DMK पर राष्ट्रवाद को लेकर कटाक्ष किया है। इसको DMK बर्दाशन नहीं कर पा रही है। दरअसल तमिलगम के जरिए DMK पर एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। DMK दलितों और गरीबों की पार्टी होने का दावा करती है, मगर तमिलगम शब्द इस बात की याद दिलाता है कि DMK तो भारत से अलग होना चाहती थी। वह तो अलग राष्ट्र की मांग की समर्थक थी। इसके अलावा DMK सिर्फ तमिलों को ही तमिलवासी मानती है, अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए उसके दिल में जगह नहीं है। हाल ही में जब तमिलनाडु के सुपर स्टर रजनीकांत के प्रदेश राजनीति में आने की सुगबुगाहट सुनाई पड़ी थी तब DMK ने तमिल फॉरं तमिलयन का नारा दिया था। ऐसे में DMK को लग रहा है कि अगर इस मामले को इसी तरह से छोड़ दिया तो उत्तर भारत की तरह बीजेपी तमिलनाडु में राष्ट्रवाद की राजनीति शुरू कर देगी, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति से उसको तमिलनाडु में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है।

